Machinery for Selection of Personnel Inspectors dealing with H.O.E.R.

7714. SHRI Y. S. MAHAJAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether as per para 347 of Award of Mr. Justice G. S. Rajadhyaksha, Personnel Inspectors dealing with Hours of Employment Regulations are required to be chosen men of special merit and well paid; and

(b) whether any machinery consisting of Senior Personnel Inspectors in highest grades as per above recommendation has been set up on Railway Divisions, for Railway Labour Tribunal 1971 work and if so, the salient features thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) In para 347 of his Award Mr. Justice G. S. Rajadhyaksha inter alia observed that the Inspectors dealing with Hours of Employment Regulations on ex-B. N. Railway were fairly well paid and that this was as it should be as the men chosen must be of special merit and able to form and express their opinions in collaboration with, and yet independently of, the Traffic and other Inspectors employed in the executive branches.

(b) The Railway Labour Tribunal 1971 has yet to submit its recommendations. The Railway Labour Tribunal 1969, however, inter alia, reviewed the Hours of Employment Regulations. Its recommendations are under consideration of Government.

विंध्य प्रदेश क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने के लिये मध्य प्रदेश सरकार का अनुरोध

7715. श्री गगां चरण दीक्षित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है विंध्य प्रदेश क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने का काम शीघ्र आरम्भ किया जावे ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हा ।

(ख) रीवा के रास्ते सतना से व्योहारी तक एक बडी लाइन जो विंध्य प्रदेश में पडती है, के निर्माण के लिये यातायात सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो गया है और उसकी रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है । रिपोर्ट की जांच हो जाने के बाद उसके निर्माण के सबध मे विनिश्चय किया जायेगा ।

ताप्ती नदी परियोजना से मिलने वाले लाभों के बारे में मध्य प्रदेश का विचार

7516 श्री गगां चरण दीक्षित : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि ·

(क) क्या मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र सरकारो द्वारा पूरी की जा रही ताप्ती नदी परियोजना से मध्य प्रदेश सरकार ने अपने पिछड़े क्षेत्रो के विकास के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के बारे मे अपने विचार व्यक्त किए हैं;

(ख) यदि हा, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस नदी परियोजना से दोनों राज्यो को होने वाले लाभों का अनुपात क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) और (ख) : महाराष्ट्र सरकार ने अपर ताप्ती परियोजना चरण-दो के लिए परियोजना रिपोर्ट हाल में भेजी है । इसकी अनुमानित लागत 87.93 करोड़ रूपये है और यह महाराष्ट्र में धुलिया जिले तथा मध्य प्रदेश के निमाड़ जिले में पिछड़े क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगी । इस परियोजना को

दोनों राज्यों के संयुक्त प्रयास के रूप में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है और यह दोनों राज्यों के बीच मई, 1969 में हुए समझौते के अनुसार है। इस स्कीम को केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में तकनीकी जांच की जा रही है।

(ग) यह परियोजना मध्य प्रदेश में 46,691 हैक्टेयर और महाराष्ट्र मे 59,849 हैक्टेयर को वार्षिक सिंचाई की व्यवस्था करेगी।

मध्य रेलवे के प्लेटफार्मों पर पेय जल की सुविधाएं

7717. श्री हुकम चन्द कछवाय क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य रेलवे मे ऐसे कितने प्लेटफार्म हैं जहा पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, और

(ख) इन प्लेटफार्मों पर यात्रियो को पेय जल की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार की भावी योजना क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) मध्य रेलवे के सभी यात्री प्लेटफार्मों पर पीने के पानी की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है।

बिहार में सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाएं

7718. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बिहार मे सिंचाई और विद्युत की कौन-कौन सी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं ;

(ख) गत दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता प्रदान की है और इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता मांगी गई थी; और

(ग) वित्तीय वर्ष 1974-75 मे इस शीर्ष के अंतर्गत राज्य सरकार को कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस समय बिहार सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही सिंचाई (वृहत व मध्यम) और विद्युत परियोजनाओ का विवरण सभा पटल पर रखे गये विवरण मे दिया गया है [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या LT/6797/74]

(ख) और (ग) चौथी योजना के दौरान राज्य योजना स्कीमो हेतु केन्द्रीय सहायता सम्पूर्ण राज्य के लिए ब्लाक ऋणो तथा अनुदानो के रूप मे दी गई थी और यह किसी परियोजना अथवा विकास शीर्ष विशेष से सम्बद्ध नही थी। बहरहाल, बिहार सरकार को उनकी 1972-73 और 1973-74 की वार्षिक योजनाओ के नियमित क्रमश: 78.88 करोड़ रुपये और 68 68 करोड रुपये की सहायता दी गई थी। उनकी 1974-75 की वार्षिक योजना के लिए 68.68 करोड़ रुपये सहायता देने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त योजना सहायता के अतिरिक्त बिहार सरकार को निम्नलिखित सहायता भी दी गई :